



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष 1933 (श0)

(सं0 पटना 836) पटना, वृहस्पतिवार, 29 दिसम्बर 2011

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

28 दिसम्बर 2011

सं0 22/नि0सि0(जम0)—12—10102/94/1617—श्री हसन मजीद, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, बराज अंचल, गालुडिह सम्प्रति सेवा—निवृत्त को गालुडिह बराज के सेकेन्ड स्टेज कंक्रिटिंग कार्य में की गयी अनयमितताओं के लिए बिहार सिविल सर्विसेज (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम—55“ए” के तहत मुख्य अभियन्ता, गालुडिह कम्प्लेक्स, आदित्यपुर के पत्रांक 988, दिनांक 29.4.92 की छाया प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 899, दिनांक 19.6.92 द्वारा श्री मजीद से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री मजीद से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाए गये।

(1) चालीस लाख रुपये का जमानत की राशि को अधूरे कार्य के बावजूद मेसर्स अरविन्द टेक्नों को लौटा दी गयी।

(2) वर्क कम्प्लीसन का जो गलत प्रमाण—पत्र कार्यपालक अभियन्ता द्वारा दिया गया, उसकी सहमति देना।

उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री मजीद, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को बिहार पेंशन नियमावली के नियम—43 बी0 के तहत विभागीय आदेश सं0 88—सह—पठित ज्ञापांक 218, दिनांक 15.1.98 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया।

(1) 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) पेंशन पर रोक।

उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री मजीद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 3054/98 दायर किया गया जिसमें दिनांक 5.2.09 को न्याय निर्णय पारित करते हुए उक्त याचिका को निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात मो0 मजीद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एल0 पी0 ए0 सं0 284/09 दायर किया गया जिसमें दिनांक 8.7.11 को पारित न्याय निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया है कि याचिकाकर्त्ता के 50 प्रतिशत पेंशन की कटौती का दण्ड बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाये बिना ही, संसूचित किया गया। उक्त विचार व्यक्त करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा श्री मजीद को 50 प्रतिशत पेंशन पर रोक से संबंधित दण्डादेश दिनांक 15.1.98 को निरस्त कर दिया गया एवं उनके विरुद्ध प्रतिवादी (सरकार) को नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई करने की छूट दी गयी। साथ ही न्याय निर्णय प्राप्ति के तीन माह के अन्दर याचिकाकर्त्ता को बकाया पेंशन राशि के भुगतान का आदेश भी दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एल0 पी0 ए0 सं0 284/09 में पारित न्याय निर्णय की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा उक्त एल0 पी0 ए0 में पारित न्याय निर्णय का अनुपालन करते हुए

याचिकाकर्त्ता श्री मजीद सेवा-निवृत्त अधीक्षण अभियन्ता को बकाये पेंशन की राशि का भुगतान करने तथा न्याय निर्णय के आलोक में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में एल0 पी0 ए0 सं0 284/09 में दिनांक 8.7.11 को पारित न्याय निर्णय का अनुपालन करते हुए श्री हसन मजीद सेवा-निवृत्त अधीक्षण अभियन्ता को 50 प्रतिशत पेंशन पर रोक से संबंधित विभागीय आदेश सं0 88-सह-पठित ज्ञापांक 218 दिनांक 15.1.98 को निरस्त किया जाता है एवं पेंशन के बकाये राशि का अविलम्ब भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

उक्त आदेश श्री मजीद सेवा-निवृत्त अधीक्षण अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अफजल अमानुल्लाह,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 836-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>